सीएम नीतीश कुमार ने की नगर विकास विभाग की समीक्षा, सूबे के 15 शहर बनेंगे स्मार्ट

नया पाटलिपुत्र बसेगा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

- राजधानी के आसपास नई टाउनशिप विकसित की जाएगी
- पटना मेट्रो को राज्य ने हरी झंडी दी, अब केन्द्र की बारी

पटना में मंगलवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पटना के अलावा 14 अन्य शहरों के लिए अलग विकास प्राधिकार बनाने एवं आयोजना क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें सभी प्रमंडलीय मुख्यालय एवं सभी नगर निगम शहर तथा बोधगया एवं राजगीर शामिल हैं। पटना मुख्य शहर के ईद- गिर्द मॉडल टाउनशिप विकसित करने और नया पाटलिपुत्र बसाने की कार्ययोजना बनाने को कंसल्टेंट की नियुक्ति करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भी तय हुआ कि शहरी गरीबों को आवास सुनिश्चित करने के लिए तथा वासभूमि एवं व्यापक पैमाने पर मल्टीस्टोरी फ्लैट्स बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए। अगले 5 वर्षों में चार लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी विभागीय योजना को प्रभावकारी बनाने के लिए कोई बदलाव करने की जरूरत है तो विभाग प्रस्ताव लाए। विभाग को सीवरेज नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट भी साथ हो। गली, नाला निर्माण के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से वेस्ट मैटेरियल अंतिम निकासी प्वाइंट तक पहुंचे। मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के स्वरूप में अगर परिवर्तन की जरूरत हो तो इसका प्रस्ताव भी लाएं।

गलत नक्शा पास न हो पेज 11

पटना का मास्टर प्लान तीन माह में पास होगा

पटना मास्टर प्लान को 3 महीने में राज्य सरकार से अनुमोदित कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 'पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी' को तत्काल कार्यरत करने का निर्णय हुआ। यह ऑथोरिटी, पटना आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पटना नगर निगम, नगर परिषदों (फुलवारीशरीफ/दानापुर/खगौल) सहित 12 नगर निकायों एवं संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण का विनियमन करेगी तथा विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन करेगी।

मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना

- वर्ष 2015-16 के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार
- उत्कृष्ट कार्य करने पर एक नगर निगम को 5 करोड़ रुपए पुरस्कार
- दो नगर परिषदों को 3-3 करोड़
- दो नगर पंचायतों को 1-1 करोड़

बड़े फैसले

- शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग योजना लागू होगी
- तीन वर्षों में सभी शहरी गरीब परिवार एसएचजी नेटवर्क से जुड़ेंगे
- इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अर्बन इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन बनेगा

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- ई-म्युनिस्पिलिटी लागू होगा
- सैरातों का ई-ऑक्शन होगा
- सभी संपदाओं की पंजी बनेगी
- सेल्फ असेसमेंट को बढ़ावा

पटना मेट्रो परियोजना मंजूर

पटना मेट्रो रेल परियोजना पर सीएम ने सहमति दे दी है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्देश दिया है।